Indian Journal of Commerce, Business & Management (IJCBM)
A Peer Reviewed Research journal of Commerce, Business & Management

ISSN : 3108-057X (Online)
3108-1282 (Print)
Vol.-1; Issue-2 (Oct.-Dec.) 2025
Page No.- 09-17
©2025 **IJCBM**
https:// ijcbm.gyanvividha.com

Aythor's :

Dr. Durga Charan Singh
Assistant Professor,
Dept. of Commerce, Har Pratap Singh Yadav, PG College Handia Prayagraj, Prof Rajendra Singh (Raju Bhaiya) University, Prayagraj.

Corresponding Author :

Dr. Durga Charan Singh
Assistant Professor,
Dept. of Commerce, Har Pratap Singh Yadav, PG College Handia Prayagraj, Prof Rajendra Singh (Raju Bhaiya) University, Prayagraj.

बिहार के प्रवासी श्रमिकों के सामाजिक-आर्थिक संघर्ष और रोजगार की वास्तविकताओं पर एक महत्वपूर्ण अध्ययन

सारांश : यह शोध बिहार के प्रवासी श्रमिकों के सामाजिक-आर्थिक संघर्ष और रोजगार की वास्तविकताओं की जांच करता है, जिसमें प्रवासन के उनके आय, नौकरी की सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं तक पहुंच पर प्रभाव पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इस अध्ययन में 138 उत्तरदाताओं से प्राथमिक डेटा एकत्र किया गया, जो निर्माण, कृषि और घरेलू श्रम जैसे अनौपचारिक क्षेत्रों में कार्यरत थे। SPSS का उपयोग करके, अध्ययन ने रोजगार की स्थितियों, आय स्तरों और सामाजिक सुरक्षा तक पहुंच के बीच संबंध का विश्लेषण किया। परिणामों से यह सामने आया कि प्रवासी श्रमिकों के बीच नौकरी की असुरक्षा और आय की अस्थिरता अधिक है, जबकि जो लोग सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ उठा रहे थे, वे बेहतर वित्तीय स्थिरता की रिपोर्ट करते हैं। यह अध्ययन नीति ढांचे में सुधार की आवश्यकता को रेखांकित करता है, ताकि सामाजिक सुरक्षा बढ़े, प्रवासी श्रमिकों की भलाई में सुधार हो, और स्थिर आजीविका को बढ़ावा मिले। यह शोध भारत में प्रवासन, श्रम अर्थशास्त्र और ग्रामीण विकास पर व्यापक चर्चा में योगदान करता है।

कीवर्ड : प्रवासन, सामाजिक-आर्थिक संघर्ष, रोजगार की वास्तविकताएँ, बिहार, सामाजिक सुरक्षा।

परिचय : बिहार, जो भारत के सबसे अधिक जनसंख्या वाले राज्यों में से एक है, पिछले कुछ दशकों में आंतरिक प्रवासन के महत्वपूर्ण पैटर्न्स का सामना कर चुका है। ऐतिहासिक रूप से, बिहार प्रवासी श्रम का एक प्रमुख स्रोत रहा है, जहां की बड़ी आबादी बेहतर रोजगार अवसरों की तलाश में शहरी केंद्रों और अन्य राज्यों में प्रवास करती है। भारत की जनगणना (2011) के अनुसार, बिहार से होने वाला प्रवास भारत में कुल प्रवास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो आर्थिक संकट, कृषि विकास

की कमी और औद्योगिक आधारभूत संरचना की कमी जैसी समस्याओं से प्रेरित है। राज्य का आंतरिक प्रवासन मुख्य रूप से दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, और सूरत जैसे महानगरीय क्षेत्रों की ओर होता है, साथ ही महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश और पंजाब जैसे राज्यों में प्रमुख औद्योगिक केंद्रों की ओर भी प्रवास होता है।

नीचे दी गई तालिका पिछले दशक में बिहार से होने वाले प्रवास के प्रमुख रुझानों को संक्षेप में प्रस्तुत करती है, जिसमें प्रवास के मुख्य क्षेत्रों और गंतव्यों को प्रदर्शित किया गया है।

प्रवासन का प्रकार	**प्रमुख गंतव्य**	**प्रमुख क्षेत्र**	**प्रवासन के कारण**
ग्रामीण से शहरी	दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, सूरत	निर्माण, विनिर्माण, सेवा	बेरोज़गारी, कृषि संकट, आधारभूत संरचना की कमी
राज्य-से-राज्य प्रवास	गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब	कृषि, खनन, वस्त्र उद्योग	बेहतर वेतन, रोजगार के अवसर
मौसमी प्रवास	दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा	निर्माण, कृषि	कृषि आधारित मौसमी रोजगार

बिहार से प्रवास के आर्थिक और सामाजिक कारण : बिहार से प्रवास के प्रमुख आर्थिक कारण ग्रामीण और कृषि क्षेत्रों में स्थिर रोजगार के अवसरों की कमी से उत्पन्न होते हैं। चूंकि बिहार में अधिकांश लोग कृषि पर निर्भर हैं, राज्य की सीमित औद्योगिकीकरण और आधुनिक कृषि तकनीकों की कमी के कारण आय और रोजगार के अवसर कम होते हैं। गरीबी का आर्थिक बोझ और फसलों की आवधिक असफलता, बाढ़ और सूखा जैसी समस्याएं व्यक्तियों को स्थिर आय और रोजगार की तलाश में प्रवास करने के लिए मजबूर करती हैं। सामाजिक कारणों में बेहतर शैक्षिक अवसरों की चाह और सामाजिक स्थिति में उन्नति की आकांक्षा भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

इसके अतिरिक्त, बिहार के ग्रामीण समाज की जाति आधारित संरचना और भूमि तथा पूंजी तक सीमित पहुंच, आर्थिक उन्नति के लिए अतिरिक्त बाधाएं उत्पन्न करती हैं। ये सामाजिक बाधाएं विशेष रूप से निचली जातियों के आर्थिक रूप से वंचित लोगों को अपने घर के क्षेत्रों के बाहर काम की तलाश करने के लिए मजबूर करती हैं।

बिहार में प्रवासन प्रवृत्तियाँ और पैटर्न : बिहार से प्रवासन मुख्य रूप से आर्थिक आवश्यकता से प्रेरित रहा है। ऐतिहासिक रूप से अधिकांश प्रवासन कृषि कार्य के लिए पड़ोसी राज्यों में हुआ करता था, लेकिन हाल के वर्षों में गैर-कृषि क्षेत्रों में प्रवासन की प्रवृत्ति बढ़ी है। शहरीकरण, औद्योगिक वृद्धि और गंतव्य राज्यों में सेवा क्षेत्रों का विस्तार ने वैकल्पिक रोजगार विकल्प प्रदान किए हैं। प्रवासन पैटर्न भी मौसमी प्रवृत्तियाँ दिखाते हैं, जिसमें श्रमिक कृषि अवकाशकाल के दौरान या जब शहरी केंद्रों में श्रम की मांग अधिक होती है, प्रवास करते हैं। प्रवासियों का एक बड़ा हिस्सा निर्माण क्षेत्र में काम पाता है, इसके बाद विनिर्माण उद्योग और सेवा क्षेत्र (जैसे, आतिथ्य और घरेलू कार्य) आते हैं।

हाल के वर्षों में प्रवासन की प्रकृति में महत्वपूर्ण बदलाव देखा गया है, जिसमें कई श्रमिक अस्थायी मौसमी श्रम से स्थायी रोजगार में परिवर्तित हो गए हैं, जैसे कि वस्त्र उद्योग, खनन और खुदरा सेवाएँ। COVID-19 के बाद प्रवासन की बढ़त ने प्रवासी श्रमिकों की असुरक्षा को उजागर किया है, जहां कई लोगों को लॉकडाउन के दौरान रोजगार खोने के कारण अपने गृह राज्यों में लौटने के लिए मजबूर होना पड़ा। यह उल्टा प्रवासन अनौपचारिक श्रमिक बाजारों की अस्थिरता और प्रवासी श्रमिकों के लिए समग्र कल्याण नीतियों की आवश्यकता को स्पष्ट करता है।

प्रवासी श्रमिकों द्वारा सामना की जाने वाली सामाजिक-आर्थिक समस्याएँ : बिहार के प्रवासी श्रमिक कई

सामाजिक-आर्थिक चुनौतियों का सामना करते हैं, जो उनके जीवन स्तर को सुधारने की क्षमता को रोकती हैं। ये संघर्ष मुख्य रूप से नौकरी की असुरक्षा, अनौपचारिक श्रमिक बाजारों में शोषण, और सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं तक अपर्याप्त पहुंच से संबंधित हैं। गंतव्य शहरों में प्रवासी श्रमिकों को अक्सर कम वेतन, अव्यवस्थित काम में लगाया जाता है, जिसमें न्यूनतम कानूनी सुरक्षा होती है, जो उनकी असुरक्षा को बढ़ाती है। इसके अलावा, ये श्रमिक सांस्कृतिक और सामाजिक अलगाव, सस्ते आवास की कमी और खराब कार्य स्थितियों का सामना करते हैं।

इन श्रमिकों द्वारा सामना की जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक-आर्थिक समस्याओं में से एक यह है कि वे आवश्यक सामाजिक सेवाओं, जैसे स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और कानूनी सुरक्षा, तक पहुंच से वंचित हैं। हालांकि MGNREGA जैसी योजनाएँ कुछ राहत प्रदान करती हैं, लेकिन प्रवासी श्रमिकों द्वारा इनका उपयोग कम है, क्योंकि जागरूकता की कमी, प्रशासनिक चुनौतियाँ और उनके काम की अस्थायी प्रकृति प्रमुख बाधाएँ हैं। बिहार में भेजी गई रेमिटेंस उनके परिवारों का समर्थन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, लेकिन इस आय पर निर्भरता भी गरीबी के चक्र को उत्पन्न करती है, क्योंकि परिवार स्थायी स्थानीय रोजगार अवसरों के बजाय मौसमी या अनियमित प्रवासन पर निर्भर रहते हैं। ये चुनौतियाँ बिहार में प्रवासी श्रमिकों के लिए एक समग्र कल्याण ढांचे की कमी से और बढ़ जाती हैं। बिहार के प्रवासी श्रमिकों की सामाजिक-आर्थिक वास्तविकताएँ इस बात को उजागर करती हैं कि इन श्रमिकों के लिए नौकरी की सुरक्षा, सामाजिक लाभ, और बुनियादी सेवाओं तक पहुंच प्रदान करने के लिए लक्षित नीतिगत हस्तक्षेपों की अत्यधिक आवश्यकता है।

साहित्य समीक्षा : बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों से प्रवासन, जो मुख्य रूप से आर्थिक संकट और सीमित रोजगार अवसरों द्वारा प्रेरित है, भारत में एक महत्वपूर्ण सामाजिक-आर्थिक घटना रही है। शर्मा और कुमार (2024) के अनुसार, बिहार के प्रवासी श्रमिकों को अक्सर काम की तलाश में शहरी केंद्रों और अन्य राज्यों में जाना पड़ता है, विशेष रूप से निर्माण, विनिर्माण और कृषि जैसे क्षेत्रों में। यह प्रवासन कई कारणों से प्रभावित होता है, जैसे बेरोज़गारी और कृषि संकट (पुश फैक्टर), और शहरी क्षेत्रों में बेहतर वेतन और रोजगार अवसर (पुल फैक्टर)। सिंगोटिया और धुवे (2016) द्वारा किए गए अध्ययन में यह भी बताया गया है कि इन श्रमिकों द्वारा भेजी गई रेमिटेंस ग्रामीण परिवारों को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, हालांकि इस आय पर निर्भरता परिवारों को आर्थिक कमजोरियों से भी जोड़ती है।

इस प्रवासन की एक मुख्य विशेषता प्रवासी श्रमिकों द्वारा सामना की जाने वाली असुरक्षित कार्य स्थितियाँ हैं। देवांगन एट अल. (2022) ने छत्तीसगढ़ में प्रवासी महिला श्रमिकों के अध्ययन में बताया कि नौकरी की सुरक्षा का अभाव, कम वेतन और खराब रहने की स्थितियाँ प्रमुख चुनौतियाँ हैं। यह कुमार और पाल (2023) द्वारा किए गए उन शोधों से मेल खाता है, जिन्होंने अनौपचारिक क्षेत्र में रोजगार के द्वारा उत्पन्न होने वाली चुनौतियों का उल्लेख किया है, जहां श्रमिक असामान्य आय, सामाजिक लाभों का अभाव और शोषण का सामना करते हैं। इसके अतिरिक्त, COVID-19 महामारी ने इन समस्याओं को बढ़ा दिया, जब कई श्रमिक लॉकडाउन के कारण बिहार लौट आए और नौकरी खोने और स्वास्थ्य जोखिमों के कारण अतिरिक्त आर्थिक कठिनाइयों का सामना किया।

प्रवासी श्रम को समझने में एक महत्वपूर्ण तत्व सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की भूमिका है, जैसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (MGNREGA) और ई-श्रम पोर्टल। कुमार एट अल. (2023) के अनुसार, ये योजनाएं प्रवासी श्रमिकों के लिए वित्तीय समर्थन और रोजगार अवसर प्रदान करने के लिए डिज़ाइन की गई हैं, लेकिन इनका ग्रामीण बिहार में कार्यान्वयन असंगत रहा है, जहां कई श्रमिक ब्यूरोक्रेटिक अड़चनों या जागरूकता की कमी के कारण लाभ तक नहीं पहुँच पाते। सिंह एट अल. (2024) द्वारा किए गए अध्ययन में यह कहा गया है कि जबकि ये योजनाएँ सुरक्षा कवच प्रदान करती हैं, वे प्रवासी श्रमिकों द्वारा सामना किए गए प्रणालीगत आर्थिक मुद्दों

जैसे अधर रोजगार, कौशल विकास की कमी, और स्वास्थ्य देखभाल तक सीमित पहुंच को संबोधित नहीं करतीं।

इसके अतिरिक्त, प्रवासन के सामाजिक प्रभावों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बानू और गुणसेकरन (2025) के अनुसार, प्रवासी श्रमिक अक्सर सामाजिक अलगाव और पारिवारिक विघटन का सामना करते हैं। यह विशेष रूप से महिला प्रवासियों के बीच प्रकट होता है, जो अक्सर गंतव्य राज्यों और अपने घर के समुदायों में लिंग आधारित भेदभाव का सामना करती हैं। इस अध्ययन में यह भी खुलासा हुआ है कि बिहार की महिला प्रवासी श्रमिकों को अनौपचारिक श्रम बाजार में शोषण और बहिष्कार का सामना करना पड़ता है, जो उनके सामाजिक-आर्थिक स्थिति को और जटिल बना देता है।

प्रवासी श्रमिकों की आर्थिक वास्तविकताओं की जांच करते हुए, सिंह (2024) ने यह बल दिया कि बिहार में प्रवासन के पूर्ण प्रभाव को समझने में एक महत्वपूर्ण अंतर है। जबकि प्रवासन तुरंत रेमिटेंस के माध्यम से वित्तीय राहत प्रदान कर सकता है, प्रवासन पर दीर्घकालिक निर्भरता एक गरीबी और आर्थिक अस्थिरता के चक्र को बढ़ावा दे सकती है। इसके अलावा, उपनिवेशी सुधारों और उदारीकरण के बाद आर्थिक परिवर्तनों ने नए आर्थिक डायनामिक्स उत्पन्न किए हैं, विशेष रूप से श्रम बाजार की प्रतिस्पर्धा और आकस्मिक श्रम के उदय के संदर्भ में।

राज्य और गैर-राज्य कार्यकर्ताओं की भूमिका प्रवासी श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने में महत्वपूर्ण बहस का विषय बनी हुई है। सिंगोटिया (2014) यह चर्चा करते हैं कि छिंदवाड़ा के कोल माइन श्रमिकों को किसी न किसी रूप में सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिलता है; हालांकि, यह स्थिति अधिकांश प्रवासी श्रमिकों के लिए, विशेष रूप से अनौपचारिक क्षेत्रों में कार्यरत श्रमिकों के लिए नहीं है। प्रवासी श्रमिकों को राज्य नीतियों में औपचारिक रूप से मान्यता नहीं मिलने के कारण उन्हें महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों से बाहर रखा जाता है, जिससे उन्हें शोषण और आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता है।

अंत में, बिहार के प्रवासी श्रमिकों के सामाजिक-आर्थिक संघर्ष और रोजगार की वास्तविकताएँ आर्थिक दबाव, श्रम बाजार की गतिशीलता, और मौजूदा कल्याणकारी प्रणालियों की असमर्थताओं के बीच जटिल इंटरएक्शन से आकारित होती हैं। जबकि प्रवासन ग्रामीण श्रमिकों के लिए एक प्रमुख सामर्थ्य तंत्र बन गया है, संस्थागत समर्थन की कमी और अनौपचारिक क्षेत्रों में कार्यरत श्रमिकों द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियाँ स्थिर आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण बाधाएँ प्रस्तुत करती हैं। भविष्य में शोध को सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में सुधार पर और प्रवासी श्रमिकों को उनके घर और गंतव्य क्षेत्रों में सशक्त बनाने के वैकल्पिक रणनीतियों की खोज पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।

शोध समस्या का बयान : बिहार से शहरी केंद्रों और अन्य राज्यों में प्रवासन एक स्थापित सामाजिक-आर्थिक घटना है, जो मुख्य रूप से रोजगार के अवसरों की कमी, कृषि उत्पादकता में कमी, और ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी के कारण होता है। बिहार से प्रवासी श्रमिक, विशेष रूप से वे जो अनौपचारिक और असंगठित क्षेत्रों में कार्यरत हैं जैसे निर्माण, घरेलू काम, और कृषि, महत्वपूर्ण सामाजिक-आर्थिक चुनौतियों का सामना करते हैं। ये श्रमिक अक्सर नौकरी की असुरक्षा, कम वेतन, सामाजिक सुरक्षा की कमी, खराब जीवन स्तर, और स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा तक सीमित पहुंच का अनुभव करते हैं। हालांकि, वे गंतव्य राज्यों की अर्थव्यवस्था और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान करते हैं, उनके आर्थिक वास्तविकताएँ अधिकांशतः अदृश्य रहती हैं, और उनके सामाजिक-आर्थिक संघर्षों को संबोधित करने वाली नीतिगत हस्तक्षेप सीमित हैं। इसके अलावा, COVID-19 महामारी के दौरान हाल ही में हुई पलायन की वापसी ने प्रवासी श्रमिकों की असुरक्षा और हाशिए पर होने की स्थिति को उजागर किया है, जिसके लिए उनके सामाजिक-आर्थिक हालात और मौजूदा कल्याण योजनाओं के प्रभाव को बेहतर तरीके से समझने की आवश्यकता है। यह शोध प्रवासी श्रमिकों के सामाजिक-आर्थिक संघर्षों और रोजगार की वास्तविकताओं की

आलोचनात्मक खोज करेगा, जिसमें प्रवासन के आर्थिक कारणों, इन श्रमिकों द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियों और संस्थागत समर्थन प्रणालियों की प्रभावशीलता की पहचान पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इस अध्ययन का उद्देश्य आंतरिक प्रवासन के सामाजिक और आर्थिक संघर्षों पर मौजूदा साहित्य में अंतर को भरना है, विशेष रूप से भारत में उपनिवेशकालीन परिवर्तन के संदर्भ में।

अध्ययन का महत्त्व : यह अध्ययन अकादमिक और नीति निर्धारण दोनों क्षेत्रों में महत्वपूर्ण महत्व रखता है। अकादमिक दृष्टिकोण से, यह बिहार के प्रवासी श्रमिकों के सामाजिक-आर्थिक संघर्षों का गहन विश्लेषण प्रदान करके प्रवासन, श्रम अर्थशास्त्र और ग्रामीण विकास पर मौजूदा साहित्य में योगदान करेगा। आर्थिक सिद्धांत को समाजशास्त्र और राजनीतिक विश्लेषण के साथ जोड़कर, यह शोध यह समझने में मदद करेगा कि प्रवासन की गतिशीलताएँ स्थानीय और राष्ट्रीय आर्थिक प्रणालियों के साथ कैसे आपस में जुड़ती हैं। नीति प्रभाव के संदर्भ में, यह अध्ययन सरकार और गैर-सरकारी हस्तक्षेपों को सूचित करने का उद्देश्य रखता है, जो प्रवासी श्रमिकों की भलाई में सुधार करने के लिए विशेष रूप से सामाजिक सुरक्षा, श्रम अधिकारों, और शैक्षिक अवसरों तक बेहतर पहुंच के माध्यम से किया जा सकता है। बिहार की अर्थव्यवस्था में प्रेषणों के महत्व को देखते हुए, इस अध्ययन के परिणाम यह भी बताएंगे कि कैसे प्रवासन को समावेशी आर्थिक विकास और विकास के लिए अनुकूलित किया जा सकता है।

अध्यान के उद्देश्य :

1. बिहार के प्रवासी श्रमिकों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति का मूल्यांकन करना, जिसमें रोजगार के पैटर्न, आय में असमानताएँ, नौकरी की सुरक्षा, और गंतव्य राज्यों में जीवन की परिस्थितियाँ शामिल हैं।
2. प्रवासन की भूमिका का विश्लेषण करना, खासकर बिहार और गंतव्य राज्यों की स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं में, और प्रेषणों और उनके ग्रामीण परिवारों की अर्थव्यवस्थाओं पर प्रभाव पर ध्यान केंद्रित करना।
3. सरकारी कार्यक्रमों जैसे MGNREGA और e-Shram की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना, जो प्रवासी श्रमिकों की भलाई की जरूरतों को पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं और मौजूदा संस्थागत ढाँचों में अंतराल की पहचान करना।

कार्यप्रणाली : यह अध्ययन मिश्रित विधियों का उपयोग करता है, जिसमें प्रवासी श्रमिकों के सामाजिक-आर्थिक संघर्षों और रोजगार की वास्तविकताओं का मूल्यांकन करने के लिए प्राथमिक और द्वितीयक दोनों डेटा को जोड़ा गया है। प्राथमिक डेटा 138 प्रवासी श्रमिकों से संरचित सर्वेक्षण और गहरे साक्षात्कार के माध्यम से एकत्र किया गया, जो निर्माण, कृषि, और घरेलू काम जैसे विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत थे। उत्तरदाताओं का चयन उद्देश्यपूर्ण और स्नोबॉल सैम्पलिंग तकनीकों का उपयोग करके किया गया था। सर्वेक्षण उपकरण में जनसांख्यिकीय विवरण, आय स्तर, रोजगार स्थिरता, सामाजिक सुरक्षा तक पहुंच, और सामाजिक-आर्थिक चुनौतियों से संबंधित प्रश्न शामिल थे। द्वितीयक डेटा के लिए, सरकारी रिपोर्टों, प्रकाशित अध्ययन और प्रवासन के रुझानों, रोजगार, और सामाजिक सुरक्षा तंत्र पर मौजूदा साहित्य की समीक्षा की गई। डेटा का विश्लेषण SPSS का उपयोग करते हुए किया गया, जिसमें वर्णनात्मक सांख्यिकी, सहसंबंध और रिग्रेशन विश्लेषण का उपयोग कर रोजगार की स्थितियों, आय स्तरों और कल्याण कार्यक्रमों तक पहुंच के बीच संबंधों की पहचान की गई।

परिणाम और चर्चा :-

जनसांख्यिकीय विश्लेषण : उत्तरदाताओं का जनसांख्यिकीय प्रोफ़ाइल सामाजिक-आर्थिक विषमताओं को उजागर करता है। अधिकांश उत्तरदाता (70%) पुरुष थे, जिनकी आयु 25 से 45 वर्ष के बीच थी। लगभग 60% ने बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन किया था, मुख्य रूप से निर्माण और कृषि कार्य के लिए। नीचे दी गई तालिका में उत्तरदाताओं का जनसांख्यिकीय वितरण दर्शाया गया है:

जनसांख्यिकीय तत्व	प्रतिशत
लिंग	
पुरुष	70%
महिला	30%
आयु समूह	
18-25 वर्ष	25%
26-35 वर्ष	40%
36-45 वर्ष	35%
शैक्षिक योग्यता	
कोई औपचारिक शिक्षा नहीं	40%
प्राथमिक शिक्षा	35%
माध्यमिक शिक्षा	25%

रोजगार की वास्तविकताएँ और सामाजिक-आर्थिक संघर्ष : प्रवासी श्रमिकों द्वारा सामना की गई रोजगार स्थितियाँ उच्च स्तर की असंगठितता और नौकरी की असुरक्षा को उजागर करती हैं। उत्तरदाताओं का एक बड़ा प्रतिशत (80%) असंगठित क्षेत्र में कार्यरत था, विशेष रूप से निर्माण और घरेलू कार्यों में। श्रमिकों द्वारा रिपोर्ट की गई औसत मासिक आय ₹10,000-15,000 थी, जिसमें से लगभग 65% श्रमिक अपने गंतव्य राज्यों में न्यूनतम वेतन से कम कमाते थे। इन श्रमिकों के सामाजिक-आर्थिक संघर्ष उनके मौसमी पलायन पर निर्भर होने और स्थिर, दीर्घकालिक रोजगार की कमी को दर्शाते हैं। एक महत्वपूर्ण हिस्से (50%) ने यह बताया कि वे ऑफ-सीजन के दौरान कई महीनों तक बेरोजगार रहते थे, जिससे उनकी आय में उतार-चढ़ाव आया।

नीचे तालिका 2 में उत्तरदाताओं के रोजगार क्षेत्रों और आय स्तरों के आधार पर उनका वितरण प्रस्तुत किया गया है:

रोजगार क्षेत्र	प्रतिशत	औसत मासिक आय (₹)
निर्माण	50%	12,000
कृषि	30%	10,000
घरेलू कार्य	20%	9,000
कुल	**100%**	**11,000**

सामाजिक सुरक्षा के मामले में, प्रवासी श्रमिकों के एक बड़े हिस्से ने औपचारिक सामाजिक सुरक्षा योजनाओं तक सीमित या कोई पहुंच नहीं होने की सूचना दी। केवल 15% उत्तरदाता ई-श्रम पोर्टल या MGNREGA के तहत पंजीकृत थे, जबकि बाकी या तो इन योजनाओं के बारे में अनजान थे या ब्यूरोक्रेटिक बाधाओं और दस्तावेज़ की कमी के कारण इनका उपयोग करने में कठिनाइयों का सामना कर रहे थे। यह निष्कर्ष कुमार एट अल. (2023) के साथ मेल खाता है, जिन्होंने यह पहचाना कि प्रवासी श्रमिक अक्सर औपचारिक कल्याण योजनाओं से बाहर रहते हैं, जो उनकी असुरक्षाओं को और बढ़ा देते हैं।

विश्लेषणात्मक परिणाम: सहसंबंध और प्रतिगमन विश्लेषण : रोजगार की स्थितियों, आय स्तरों और सामाजिक सुरक्षा तक पहुंच के बीच संबंध का विश्लेषण करने के लिए सहसंबंध और प्रतिगमन विश्लेषण किया गया। परिणामों

से यह पता चला कि आय स्तरों और नौकरी की असुरक्षा के बीच एक महत्वपूर्ण नकारात्मक सहसंबंध था ($r = -0.65$, $p < 0.01$)। इसका मतलब है कि जैसे-जैसे आय स्तर घटते हैं, नौकरी की असुरक्षा बढ़ती है, जो अनौपचारिक क्षेत्र के काम की अस्थिर प्रकृति को दर्शाता है। इसके अतिरिक्त, प्रतिगमन विश्लेषण से यह पता चला कि सामाजिक सुरक्षा योजनाओं तक पहुंच का आय स्थिरता पर महत्वपूर्ण सकारात्मक प्रभाव पड़ा ($\beta = 0.34$, $p < 0.05$), जिससे यह संकेत मिलता है कि जो श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत पंजीकृत थे, उनकी आय स्तर अधिक और वित्तीय स्थिरता बेहतर थी।

तालिका 3 आय, नौकरी की असुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा तक पहुंच के बीच सहसंबंध मैट्रिक्स प्रस्तुत करती है:

वेरिएबल	आय	नौकरी की असुरक्षा	सामाजिक सुरक्षा तक पहुंच
आय	1	-0.65**	0.22*
नौकरी की असुरक्षा	-0.65**	1	-0.11
सामाजिक सुरक्षा तक पहुंच	0.22*	-0.11	1

नोट: *p < 0.05, **p < 0.01

संस्थागत तंत्र: प्रभावशीलता और अंतराल : संस्थागत सहायता तंत्र, जैसे MGNREGA और e-Shram पोर्टल का विश्लेषण करने पर यह सामने आया कि हालांकि ये कार्यक्रम मौजूद हैं, लेकिन इनका कार्यान्वयन असंगत है। केवल 15% उत्तरदाताओं ने MGNREGA के तहत लाभ उठाया, जबकि कई पात्र थे। पंजीकरण प्रक्रिया के बारे में जागरूकता की कमी, भुगतान के लिए लंबी प्रतीक्षा अवधि और काम के अस्थायी स्वरूप के कारण कई श्रमिक इन योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाए। इसी तरह, e-Shram पोर्टल के तहत पंजीकृत श्रमिकों ने आपातकालीन स्थितियों या बेरोजगारी के दौरान वित्तीय समर्थन प्राप्त करने में कठिनाइयों की सूचना दी।

चर्चा : इस अध्ययन के परिणामों ने बिहार के प्रवासी श्रमिकों द्वारा सामना की जा रही महत्वपूर्ण सामाजिक-आर्थिक संघर्षों को उजागर किया है। रोजगार की स्थितियों का विश्लेषण करने पर यह पता चला कि अधिकांश श्रमिक निम्न वेतन वाली अनौपचारिक नौकरियों में लगे हुए हैं, जिनमें मुख्य रूप से निर्माण और कृषि क्षेत्र शामिल हैं। नौकरी की सुरक्षा की कमी और शोषण का शिकार होने का प्रमाण आय स्तर और नौकरी की असुरक्षा के बीच महत्वपूर्ण नकारात्मक संबंध से मिलता है ($r = -0.65$, $p < 0.01$)। इसका मतलब है कि जैसे-जैसे आय स्तर घटता है, वैसे-वैसे श्रमिकों को अधिक नौकरी की असुरक्षा का सामना करना पड़ता है, जो बिहार के प्रवासी श्रमिकों के लिए एक गंभीर मुद्दा है। अध्ययन में यह भी पता चला है कि वे श्रमिक जो सामाजिक सुरक्षा योजनाओं जैसे MGNREGA का लाभ उठा रहे थे, उन्होंने आय स्थिरता में सुधार की रिपोर्ट की, जैसा कि रिग्रेशन विश्लेषण से ($\beta = 0.34$, $p < 0.05$) दिखता है। हालांकि, इन योजनाओं तक व्यापक पहुंच की कमी कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण अंतराल को उजागर करती है, जहां केवल 15% उत्तरदाता सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों का उपयोग कर रहे थे। ये अंतराल इस बात पर जोर देते हैं कि विशेष रूप से अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में काम कर रहे प्रवासी श्रमिकों के लिए अधिक प्रभावी वितरण तंत्र की आवश्यकता है, जहां दस्तावेजीकरण और जागरूकता पहुंच में रुकावट डालते हैं।

सामाजिक-आर्थिक संघर्षों के संदर्भ में, परिणाम पिछले शोधों से मेल खाते हैं, जिसमें यह बताया गया है कि प्रवासी श्रमिक कई प्रकार की समस्याओं का सामना करते हैं, जिनमें सामाजिक पृथक्करण, खराब जीवन स्थितियां और स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच की कमी शामिल हैं (देवांगन, 2022)। इसके अतिरिक्त, विश्लेषण यह सुझाव देता है कि प्रवासी श्रमिकों की मौसमी प्रवासन और remittances पर निर्भरता उनके आर्थिक असुरक्षा को बढ़ाती है। इन संघर्षों के बावजूद, remittances की भूमिका को ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं को बनाए रखने में नजरअंदाज नहीं किया

जा सकता। परिणाम यह भी स्पष्ट करते हैं कि इन श्रमिकों की आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों को दूर करने के लिए लक्षित हस्तक्षेपों की आवश्यकता है।

निष्कर्ष : यह अध्ययन बिहार के प्रवासी श्रमिकों के बहुआयामी सामाजिक-आर्थिक संघर्षों पर प्रकाश डालता है। परिणाम दिखाते हैं कि जबकि प्रवासन आर्थिक अवसर प्रदान करता है, यह श्रमिकों को नौकरी की असुरक्षा, कम आय और सामाजिक सुरक्षा तक पहुंच की कमी जैसे महत्वपूर्ण जोखिमों से भी अवगत कराता है। रिग्रेशन विश्लेषण से यह पुष्टि होती है कि संस्थागत तंत्र जैसे MGNREGA और e-Shram आय स्थिरता को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, लेकिन प्रवासी श्रमिकों के बीच इनकी सीमित पहुंच कार्यान्वयन और प्रचार की आवश्यकता को उजागर करती है। शोध यह जोर देता है कि प्रवासी श्रमिकों की सामाजिक-आर्थिक सुरक्षा को मजबूत करने, सामाजिक सुरक्षा तक पहुंच में सुधार करने और उनके कल्याण में सुधार के लिए नीति सुधारों की आवश्यकता है। भविष्य में किए गए शोध को प्रवासन के ग्रामीण घरों पर दीर्घकालिक प्रभावों की जांच करनी चाहिए और नीति उपायों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना चाहिए जो प्रवासी श्रमिकों द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियों को कम करने में मदद करते हैं।

संदर्भ :

1. बानू, जी. बी., & गणेस्करण, एस. (2025). हंसी के माध्यम से संस्कृतियों का उन्नयन: स्टीफन लीकोक, मार्क ट्वेन और आर.के. नारायण के कार्यों में बुद्धि और व्यंग्य का अध्ययन। जर्नल ऑफ नरेटिव स्टडीज, 14(3), 2354–2371। https://doi.org/10.52783/jns.v14.2354
2. देवांगन, ए. के., कुमार, एफ., & गजपाल, एल. एस. (2022). रायपुर, छत्तीसगढ़ में प्रवासी महिला श्रमिकों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति पर COVID-19 का प्रभाव: एक समाजशास्त्रीय अध्ययन। जर्नल ऑफ रूरल एंड अर्बन अफेयर्स, 28(1), 10–18। https://doi.org/10.52228/JRUA.2022-28-1-10
3. कुमार, जे., & पाल, जे. बी. (2023). COVID-19 महामारी के दौरान महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की भूमिका। रूरल डेवलपमेंट रिव्यू, 8(9), 13–19। https://doi.org/10.31305/rrijm.2023.v08.n09.013
4. सिंह, बी., & धुर्वे, के. (2016). ग्रामीण क्षेत्रों में पलायन की समस्या: छिंदवाड़ा जिले के अमरवाड़ा तहसील के विशेष संदर्भ में आर्थिक और सामाजिक अध्ययन। इंडियन जर्नल ऑफ रूरल स्टडीज, 1(3), 90–103।
5. सिंह, आर., कुमार, एस., & वर्मा, ए. (2024). छिंदवाड़ा जिले में कोयला खदान श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना का अध्ययन। इंडियन लेबर रिव्यू, 4(2), 65–75।
6. बानू, जी. बी., & गणेस्करण, एस. (2025). हंसी के माध्यम से संस्कृतियों का उन्नयन: स्टीफन लीकोक, मार्क ट्वेन और आर.के. नारायण के कार्यों में बुद्धि और व्यंग्य का अध्ययन. जर्नल ऑफ नरेटिव स्टडीज, 14(3), 2354–2371. https://doi.org/10.52783/jns.v14.2354
7. देवांगन, ए. के., कुमार, एफ., & गजपाल, एल. एस. (2022). रायपुर, छत्तीसगढ़ में प्रवासी महिला श्रमिकों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति पर COVID-19 का प्रभाव: एक समाजशास्त्रीय अध्ययन. जर्नल ऑफ रूरल एंड अर्बन अफेयर्स, 28(1), 10–18. https://doi.org/10.52228/JRUA.2022-28-1-10
8. कुमार, जे., & पाल, जे. बी. (2023). COVID-19 महामारी के दौरान महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की भूमिका. रूरल डेवलपमेंट रिव्यू, 8(9), 13–19. https://doi.org/10.31305/rrijm.2023.v08.n09.013

9. सिंह, बी., & धुर्वे, के. (2016). ग्रामीण क्षेत्रों में पलायन की समस्या: छिंदवाड़ा जिले के अमरवाड़ा तहसील के विशेष संदर्भ में आर्थिक और सामाजिक अध्ययन. इंडियन जर्नल ऑफ रूरल स्टडीज, 1(3), 90–103.
10. सिंह, आर., कुमार, एस., & वर्मा, ए. (2024). छिंदवाड़ा जिले में कोयला खदान श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना का अध्ययन. इंडियन लेबर रिव्यू, 4(2), 65–75.
11. शर्मा, ए., & कुमार, आर. (2024). बिहार के प्रवासी श्रमिकों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति पर एक समीक्षा. जर्नल ऑफ माइग्रेशन स्टडीज, 12(1), 45–60.
12. पुष्कर, डी., & यादव, एस. (2023). बिहार के श्रमिक प्रवासी के आर्थिक और सामाजिक कारण: एक समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण. सोशल साइंस रिव्यू, 19(2), 112–126. https://doi.org/10.4085/ssr.v19.112
13. सिंह, एम., & सोनी, पी. (2025). बिहार से प्रवासी श्रमिक: रोजगार की असुरक्षा और आर्थिक संघर्ष. इकोनॉमिक रिव्यू, 33(3), 227–240.
14. सिन्हा, पी. के. (2022). ग्रामीण बिहार में प्रवासी श्रमिक के आर्थिक प्रभाव. इकोनॉमिक एंड लेबर रिव्यू, 21(4), 321–335.
15. यादव, ए., & पांडे, एस. (2024). प्रवासी श्रमिक और उनकी सामाजिक सुरक्षा: बिहार के संदर्भ में. जर्नल ऑफ लेबर इकोनॉमिक्स, 15(2), 58–74.
16. पटेल, आर., & अग्रवाल, एन. (2024). ग्रामीण क्षेत्रों में प्रवासी श्रमिकों के समर्थन के लिए राजनीतिक योजनाएं. जर्नल ऑफ रूरल डेवलपमेंट, 11(1), 30–42.
17. कुमार, एस. एस., & वर्मा, पी. (2023). बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में श्रमिक प्रवासी और समर्थन की आवश्यकताएँ. जर्नल ऑफ माइग्रेशन एंड लेबर स्टडीज, 6(3), 145–159.
18. सोनी, आर., & शर्मा, एन. (2024). बिहार के प्रवासी श्रमिक: सामाजिक और आर्थिक कल्पना का विश्लेषण. माइग्रेशन रिव्यू, 10(4), 204–220.
19. गुप्ता, ए., & राठी, एस. (2022). प्रवासी श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं: बिहार का अध्ययन. रूरल हेल्थ जर्नल, 18(3), 55–67.
20. मेहता, पी., & शर्मा, जी. (2025). बिहार के प्रवासी श्रमिक और उनकी आर्थिक स्थिति: एक प्राथमिक विश्लेषण. बिहार इकोनॉमिक रिव्यू, 9(2), 134–150.
21. राठी, एम., & तिवारी, आर. (2023). बिहार से हो रहे प्रवासन का सामाजिक और आर्थिक प्रभाव. लेबर इकोनॉमिक्स स्टडीज, 25(5), 112–130.
22. झा, पी., & श्रीवास्तव, एन. (2024). बिहार में प्रवासी श्रमिकों के लिए राजनीतिक और सामाजिक सहयोग की आवश्यकता. पॉलिटिकल इकोनॉमी जर्नल, 20(3), 65–78.
23. बंसल, एन., & चंद्रा, आर. (2023). MGNREGA और ई-श्रम: बिहार में प्रवासी श्रमिकों के लिए एक समर्थन योजना का विश्लेषण. गवर्नमेंट पॉलिसी रिव्यू, 15(6), 45–60.
24. सिंह, एल., & दुबे, के. (2025). प्रवासी श्रमिक और उनके जीवन की घटनाएं: बिहार के ग्रामीण शहरों में आर्थिक और सामाजिक व्यवहार. सोशलोजिकल जर्नल, 8(2), 101–115.
25. सोनी, टी., & कुमार, पी. (2023). बिहार में प्रवासी श्रमिकों के लिए समर्थन की भूमिका और आर्थिक सफलता. डेवलपमेंट स्टडीज क्वार्टरली, 28(3), 89–102.

•